India organisations of employers and labour have been asked to nominate their representatives on it. Representatives of Government, employers and labour will collectively co-opt on it the representatives of other interests.

(c) Finances for the productivity programme will comprise grants by the Government of India, anticipated allotment from Technical Assistance Fund of U.S. Government, and contribution by industry and other organisations in the form of subscriptions to Local Productivity Councils.

Shri N. R. Munisamy: May I know who is likely to be the Chairman of this Council?

Shri Manubhai Shah: For the present, the Minister of Industry has been nominated as the President of the Council.

Shri Ramanathan Chettiar: May I know whether the representatives from trade, commerce and industries would be represented on this Council?

Shri Manubhai Shah: Eleven members from each—government, labour and employees, and 27 from other industries and interests.

Shri S. M. Banerjee: May I know whether the central trading organisations have been asked to send their nominees?

Shri Manubhai Shah: Yes, Sir.

Shri Ranga: In view of the fact that this Council will be granted subsidies and funds by Government and also by various other organisations, have the Government considered the advisability of nominating the Minister himself to be the Chairman since there would be nobody else to examine the financial proposals that may be adopted by this Council?

Shri Manubhai Shah: Question of finance is not so important here, because the amount to be spent is not of a high order. The real point that all the organisations felt is that as it is being initiated for the first time in this country and the movement has a great potential for increasing productivity without investment, it would be better for some time at least that the Minister of Industry is the President of the Council.

Shri N. R. Munisamy: What is the amount given by the U.S. Technical Assistance Fund and how much has been provided in the second Five Year Plan?

Shri Manubhai Shah: As the hon. Member knows, it was not specifically provided in the Second Five Year Plan. But later, discussions took place with the different productive movements of different countries, and it is being initiated only this year. The grant of money and the amount will be known as the movement gathers momentum during the current year.

Shri Achar: Will agriculturists be represented on this Council?

Shri Manubhai Shah: As is well known, for the present, we are only tackling the industrial part of the productivity movement.

Shri Naushir Bharucha: What procedure is proposed to be adopted to keep Parliament informed of the progress and activities of the Productivity Council?

Shri Manubhai Shah: Like any other body set up by the Government, the House will always be informed periodically about the progress of this movement.

समाचार पत्रों के लिये मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची

\+

*१३. श्री भक्त दर्शन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ११ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच समाचार पत्रों के लिये मूल्यानुसार पृष्ठ-सूची को लागू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां,तो क्या उस सम्बन्धित आदेश की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जावेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध में जो अधिनियम है, वह कई महीने पहले स्वीकार किया जा चुका है और ससद् मे इस विषय मे कई प्रश्न पूछे जा चुके है। मै मत्री महोदय से जानना चाहता हू कि वे कौन से विशेष कारण हैं, जिनके कारण इस विषय मे इतनी देरी हो रही है?

डा० केसकर यह मामला बडा महत्वपूर्ण है और इसमे मत-भेद बहुत तीव्र है । भिन्न भिन्न अखबारो के जो ग्रुप है उन सब की राय अलग अलग है । ऐसे मामले मे सब से विचार-विनिमय किये बिना किसी नतीजे पर पहुचना हम उचित नही समझते ।

श्री भक्त दर्शन क्या माननीय मत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस प्रश्न को समाप्त करने की आशका हो गई है, या इस के बारे मे कोई आशा की जा सकती है ?

डा० केसकर · इसके बारे मे पूरी आशा की जा सकती है ।

Shri D. C. Sharma: When was the last attempt made by the Ministry to arrive at some kind of agreement with the newspaper men on this subject?

Dr. Keskar: I am not able to give the definite date when an attempt was made. Attempts were made three times and we found that it was not possible not only to have an agreed solution, but to have solutions which are near each other. The differences of opinion are very acute and we are pursuing and exchanging opinions with various groups of interests.

श्री म० ला० द्विवेदी : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि विभिन्न अखबारो के ग्रुपों से विचार-विनिमय के पश्चात कोई समझौता हो सकता है । मैं जानना चाहता हूं कि इस विचार-विनिमय में अब तक क्या प्रगति हुई है और इस मे कब तक समझौता होने की सम्भावना है ?

डा० केसकर मे ने यह नही कहा कि समझौता की सम्भावना है । मे ने कहा कि सरकार को कोई निर्णय लेने में समय लग रहा है । समझौता करने की कोशिश हम ने शुरू मे की, लेकिन कोई समझौता सम्भव नही हुआ और इसी लिये अगर हम कोई कदम आगे रखते है, कोई निर्णय करते है तो वह सोच समझ कर करना चाहिये ।

Shri Jaipal Singh: Are we to understand that the analytical investigation of the Press Commission has been of no assistance to the Government all these years?

Mr Speaker: That is a question of opinion.

Shri T. N. Singh: In view of the shortage of foreign exchange and inability to import newsprint, is it not desirable that even in the absence of any agreement by the parties concerned a price-page schedule should be introduced?

Dr. Keskar: That is an entirely separate question and it is possible that such a course might be desirable. But a price-page schedule with the objective of conserving newsprint would not be of the same type as one which is meant to avoid what might be called as a wrong type of competition of newspapers.

श्री भक्त दर्शन · क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि इतने दिनो तक इस प्रश्न का निर्णय न होने के कारण छोटे समाचारपत्रों को बडी हानी उठानी पड रही है ? और क्या उन को किसी प्रकार की सहायता देने के बारे मे विचार किया जा रहा है ?

डा० केसकर : अखबारों का सब से बड़ा सवाल हमारे सामने यह पेश था कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट की वजह से उन पर बड़ा भारी बोझा पड़ रहा है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट का सारा सवाल इस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश है। और जो अखबारों का खास दबाव था, हमारे सामने जो इनसिस्टेंस था, वह इस समय नहीं है, लेकिन हम स्वतंत्र रूप से इस मामले का जल्द से जल्द निर्णय करना चाहते हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस के बारे में समाचारपत्र संम्पादक मंडली ने कोई प्रस्ताव पास किया है ?

डा० केसकर . एक प्रस्ताव उन की तरफ़ से हुआ है, लेकिन मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि हम सब मत-मतान्तर, जितने भी इस बारे में दिये जाते हैं, को ध्यान से देखते हैं, लेकिन इस में मुख्यतः जो अखबारों-समाचारपत्रों के मालिक हैं, उन्हीं से हमारी बात-चीत हो रही है, क्योंकि अखबार का जो मूल्य है, वह उसके मालिक ही तय करते हैं ।

Shri Ansar Harvani: Question No. 45 may be taken up along with Question No. 14.

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra): That might be answered separately.

Mr. Speaker: Question No. 14 only may be answered now.

पोलैंड के साथ व्यापार

*१४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पोलैंड के बीच हुये व्यापार करार के फलस्वरूप व्यापार में किस हद तक वृद्धि होने की आशा है; और

(ख) पोलैंड को निर्यात किये जाने वाले कच्चे लोहे के बदले में भारत में कितने मूल्य की किन-किन वस्तुओं का आयात होगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) विदेशी व्यापार की उन्नति कई बातों पर निर्भर है और उस की वृद्धि करने के अनेक उपायों में इस प्रकार का करार केवल एक उपाय है। इस करार के पहले ही वर्ष यानी १९५६-५७ में भारत - पोलैंड व्यापार में पिछले साल की अपेक्षा आयात दस गुना और निर्यात चार गुना हुआ।

(ख) यह आवश्यक नहीं है कि कच्चे लोहे का निर्यात किन्हीं खास वस्तुओं के आयात के बदले में ही हो ।

Shri T. B. Vittal Rao: The answer may be read out in English.

Mr. Speaker: Yes.

Shri Satish Chandra: (a) Trade Agreement is only one of the means to facilitate foreign trade which is influenced by a number of factors. However, trade between India and Poland during the first year (1956-57) of the current Trade Agreeent increased ten times in the case of imports and four times in the case of exports over that of the previous year.

(b) Exports of iron ore are not necessarily tied up with imports of any specified goods.

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि भारत में कच्चा माल भेजे जाने के बारे में जो करार हुआ है, क्या उसके अलावा और कोई माल भेजे जाने के बारे में तय हुआ है ? यदि हां, तो कौन सा माल ?

श्री सतीश चन्द्र : इस तरह के जो भी करार हुए हैं, उन की प्रतिलिपियां लाइब्रेरी में रख दी गई हैं। उस एग्रीमेंट के अनुसार ४३ चीजें ऐसी हैं, जिन को पोलैंड से इम्पोर्ट करने का हमारा इरादा था। ३८ आइटम्स एक्सपोर्ट के थे। इस में कुछ घटे और बढ़े भी हैं। अब